IJAER/Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

''भारतीय सुरक्षा में बांग्लादेश की वर्तमान समस्या का अध्ययन''

Dr. Satish Chandra Joshi
Dept. of Military Science, (Govt. P.G. College)
Pithoragarh (Uttrakhand)

सरांश :

14 अगस्त, 1947 को जन्मा पूर्वी पाकिस्तान 24 वर्षों के अंतराल में बांग्लादेश नामक स्वतंत्र राष्ट्र भी बन गया जिसे इस राष्ट्र के भौगोलिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। लगभग 143998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत इस देश की आबादी लगभग 13 मिलियन है भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम और त्रिपुरा राज्य इस देश की क्रमशः पश्चिमी उत्तरी एवं पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी इस देश के चरणों को धोती है तथा सुदूर दक्षिण पूर्व में म्यामार इस देश से लगा हुआ है कि भारतीय उप–महाद्वीप के पूर्वी पार्श्व पर स्थित बांग्लादेश दक्षिणीपूर्वी एशिया के चौराहे की महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित चुम्बी सिलीगुड़ी गलियारे से ही नेपाल के साथ चीन की निकटता बांग्लादेश के भू–स्त्रातेजिक महत्व को और बढ़ा देती है। भारत के साथ बांग्लादेश की संलग्न लगभग 3901 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्थित राज्य विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र (The Land of Seven Sisters) की सुरक्षा में इस देश की महत्त्वपूर्ण सामरिक संलग्नता इसकी स्त्रातेजिक उपादेयता को और बढ़ा देती है। भारत–बांग्लादेश के मध्य खुली सीमाओं का ही आज यह परिणाम है कि भारत में लगभग 20 मिलियन बांग्लादेशी घुसपेठिये भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर चुके है। मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद बाबजूद यहाँ 12 प्रतिशत हिन्दू आबादी है जो धीरे–धीरे कम होती जा रही है। जिस पर आज की भारत की सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

मुख्य शब्द : बंगाल में आतंकबाद, चीन भाषा, शिलीगुडी शलिनारा, बांग्लादेश की पूर्वी सीमा आदि।

प्रस्तावना :

दक्षिण एशिया के सामरिक–राजनैतिक परिदृश्य में बांग्लादेश की भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के बदलते भू–राजनैतिक परदृश्य में बांग्लादेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नांकित बिंदू विशेष रूप से आज उल्लेखनीय है। पाकिस्तान का पूर्व भू–भाग एवं मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र होने के कारण आज भी पाकिस्तान की भारत–विरोधी रणनीति में बांग्लादेश की विशिष्ट भूमिका पूछती है।

भारत का यह पड़ोसी राष्ट्र भारत के विरूद्ध पाकिस्तान का प्रमुख उपकरण बना हुआ है। बांग्लादेश में सक्रिय भारत–विरोधी तत्व दोनों के मैत्रीपूर्ण व सहयोगी संबंधों में अवरोधक है। पाकिस्तान की ही भाँति इस्लामिक चरमपंथियों के प्रभाव में आने के कारण यहाँ भारत–गतिविधियों को ऊर्जा मिलती रहती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही इंसरजेंसी के आधार भूमि (Base) के रूप में बांग्लादेश का प्रयोग वाह्य शक्तियां आज कर रही है। चीन–बांग्लादेश के मध्य स्थापित सामरिक–आर्थिक धुरी भारतीय हेतु नयी चुनौती है। एक छोटा राष्ट्र होने के बाबजूद बांग्लादेश भारत के विरूद्ध चीन–पाक षडयंत्रों में शामिल होने हेतु उत्सुक रहता है। यह बात आज भारत की परेशानी बड़ा रहा है।

चीन–बांग्लादेश का रक्षा सहयोग और भारतीय सुरक्षा

बांग्लादेश के रक्षा तंत्र के विकास में आज चीन की प्रमुख भूमिका रही है। बांग्लादेश को भारतीय प्रभाव से विमुख करने हेतु चीन ने 23–27 दिसम्बर, 2002 को सम्पन्न बेगम खालिदा की चीन यात्रा के दौरान एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ–साथ उसे अपनी सुरक्षा–छतरी (Defence Umbrella) उपलब्ध कराने का चीन द्वारा आश्वासन दिया गया। चीन–बांग्लादेश के मध्य स्थापित उक्त रक्षा सहयोग में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की विशिष्ट उत्प्रेरक की भूमिका थी जिन्होंने अक्टूबर, 2002 में सम्पन्न अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान इसकी पृष्ठभूमि तैयार करके यह इच्छा प्रकट की थी कि भारत के साथ भावी संघर्षों में वह भारत–विरोधी मोर्चे के निर्माण हेतु संकल्पित है। बांग्लादेश–चीन के मध्य स्थापित रक्षा संबंध भारतीय सुरक्षा निम्नांकित कारणों से आज महत्त्वपूर्ण हैं –

1. दक्षिण एंशिया में चीन के हस्तक्षेप का पथ अपेक्षाकृत सुगम हो जायेगा।
2. बांग्लादेश की सैन्य सामर्थ्य बढ़ने से भारत पर राजनैतिक–सामरिक दबाब बढ़ेगा।
3. भविष्य में भारत–पाक अथवा भारत–चीन संघर्षों में चीन–पाक–बांग्लादेश सैन्य दुरभिसंधि का भारत पर सामरिक व मनोवैज्ञानिक दबाब पडेगा।
4. बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चीन के नौ सैन्य विस्तार को त्वरित आयाम मिलेगा।
5. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामरिक भेद्यता (Strategic Vulnerabilities) और भी जटिल हो जायेगी।
6. भारत द्वारा चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तारित आई0आर0बी0एम0 (IRBM) की सुरक्षा व उनका रख–रखाव प्रभावित होगा।

उक्त निहित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 2006 में चीन ने न केवल बांग्लादेश पुलिस को आवश्यक हथियार व अन्य साजो सामान उपलब्ध कराये अपितु बांग्लादेश ने चीन से 16–एफ–7, बी0जी0 फाइटर विमान भी खरीदे। मई, 2006 में बांग्लादेश के सेना प्रमुख व चीन के रक्ष ामंत्री के मध्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हुए विचार–विमर्श से दोनों देशों की रक्षा–मैत्री भावना को नयी ऊर्जा मिली। जनवरी, 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की नयी दिल्ली यात्रा के बाद सम्पन्न उनकी चीन यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि वे बांग्लादेश के महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक महत्त्व के कारण एशिया की दो उभरती हुए शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित कर अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा के दौरान चीन, म्यामार के रास्ते से रेल संपर्क द्वारा चटगांव तक अपनी पहुँच हेतु किए गए समझौते से यह संकेत मिल रहे हैं कि वह हिंद महासागर में अपनी प्रभावी रक्षा व व्यापार भूमिका हेतु चटगांव बंदरगाह के निष्कंटक प्रवेश हेतु नपी–तुली राजनयिक कोशिश कर रहा है। जिससे वह 'मलक्का स्ट्रेट' मार्ग पर अपनी निर्भरता को न्यून कर सके। उल्लेखनीय है कि सन् 2008 में चीन की सहायता से बांग्लादेश द्वारा चटगांव बंदरगाह के निकट मिसाइल लांच स्टेशन के स्त्रातेजिक महत्त्व को भारत किसी भी दशा में नकार नहीं सकता। इतना ही नहीं, बांग्लादेश द्वारा चीन को चटगांव बंदरगाह के उपयोग की अनुमति देने से भारतीय सुरक्षा हेतु गंभीर व दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिससे चीन ने बांग्लादेश के पारस्परिक रक्षा सहयोग में अभिवृद्धि करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा तनाव में अभिवृद्धि की ही कांशिश की है। और एक शक्तिशाली व समृद्ध बांग्लादेश के निर्माण में चीन उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर दक्षिण एशिया में अपने विश्वसनीय सहयोगी राष्ट्र के रूप में स्थापित करके भारतीय प्रभाव को शिथिल करना चाहता है। इसीलिए शिक्षा, संस्कृति, व्यापार व रक्षा क्षेत्रों में चीन बांग्लादेश की हर संभव सहायता कर रहा है। यद्यपि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में चीन का सबसे बड़ा तीसरा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है किन्तु यह संतुलन अधिकांशतः चीन के ही पक्ष में झुका हुआ है। 8 अप्रैल, 2005 में चीन के राष्ट्रपति जियाबाओ की बांग्लादेश यात्रा के दौरान पारस्परिक संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से दोनों राष्ट्रों के मध्य 'एशिया–प्रांत मुक्त व्यापार समझौते (AFTA) के अन्तर्गत सम्पन्न एक समझौते में ढाका व बीजिंग ने सीधे हवाई व्यापार हेतु अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। कमिंग–चटगांव सड़क (म्यांमार के रास्ते से) सम्पर्क द्वारा भी दोनों देशों ने व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किया है। इस यात्रा के दौरान चीन ने बांग्लादेश में डाई एल्युमुनियम फास्फेट (DAP) उर्वरक फक्ट्री चटगांव में स्थापित करने की भी सहमति प्रदान की। सन् 2007 में चीन के उप वाणिज्य मंत्री बांग चाओं ने बांग्लादेश की यात्रा करके जहाँ एक और उसे 50 मिलियन डालर मूल्य के बांग्लादेशी सामानों की खरीद हेतु सहमति प्रकट की

वहीं दोनों राष्ट्रों के मध्य ढाका में बांग्लादेश–चीन मैत्री प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना का भी पथ प्रशास्त हुआ। चीन, बांग्लादेश को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, जूते, शीशे के सामान, प्लास्टिक–उत्पाद, खिलौने व विभिन्न खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त सूती धागे, मशीनें, रसायन एवं उर्वरक उद्योग हेतु आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है। सन् 2010 में यह निर्यात 820 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया जबकि बांग्लादेश ने उक्त अवधि में 20 मिलियन डॉलर मूल्य के विभिन्न का चीन को निर्यात किया है। आज उल्लेखनीय है कि सन् 2009 में द्विपक्षीय व्यापार 4. 58 मिलियन डॉलर का था जिसे अब तक 5 विलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। धोखेवाज चीन द्वारा बांग्लादेश के लगभग 5000 उत्पादों को आयात कर मुक्त घोषित करके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को त्वरित गति प्रदान करने की भी घोषण की है। शेख हसीना के शासन काल में चीन ने बांग्लादेश में भारी निवेश का वचन दिया है तथा जलवायु–परिवर्तन के अतिरिक्त उग्रवाद–उन्मूलन जैसे मुद्दों पर सहयोग हेतु भी सहमत हो गया है। चीन–बांग्लादेश के बढ़ रहे आर्थिक व सामरिक संबंधों की प्रगाढ़ता का ही यह आज परिणाम है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया आदि की भाँति चीन को भी सार्क (SARRC) के पर्यवेक्षक के रूप में विशेष सक्रिय अभिरूचि प्रदर्शित करने की इच्छा प्रकट की है। बांग्लादेश व चीन के मध्य स्थापित सामरिक–प्रगाढ़ता भारतीय सुरक्षा हेतु गम्भीर चुनौतियों उत्पन्न हो सकती है –

निष्कर्ष :

200 किलोमीटर लंबे एवं 40 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी गलियारे द्वारा भारत से संलग्न भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निकट चीन की बढ़ती सामरिक गतिविधियों से 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अरूणांचल प्रदेश पर अधिकार करने की चीनी महत्त्वकांक्षाऐं सुदृढ़ होती जायेगी। इतना ही नहीं सिलीगुड़ी गलियाारे को त्वांग से जोड़कर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की चीनी गतिविधियों को सुगमता होगी तथा भूटान उसके इस लक्ष्य को और भी सुगम बनायेगा। जो भारत के हतिकारक नहीं होगा।

सिलीगुड़ी गलियारे क्षेत्र में सक्रिय 'उल्फा' व अन्य अराजक तत्वों के लिए बांग्लादेश सुरक्षित भरण स्थली है तथा यहाँ दोनों के मध्य विकसित समीकरण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र इन्सरजेन्सी को उत्प्रेरित कर सकता है।

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बांग्लादेश द्वारा चीन को दी जा रही नौ सैन्य – सुविधाऐं भारत के 'अंडमान निकोबार' द्वीप समूह की सुरक्षा एवं व्यापारिक हितों को संकटापन्न करेंगे।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (SARRC) के पर्यवेक्षक के रूप में चीन की सक्रियत को बांग्लादेश का प्रोत्साहन भारत के भू–राजनीति व क्षेत्रीय आर्थिक–हितों पर नरात्मक प्रभाव डाल सकता है।

सन्दर्भ :

1. Subhash Kapila, Bangla Desh – China Defence Cooperation, Agreements Strategic Implications : An Analysis South Asia Analysis Group, P-96
2. Ghose Snchiti, China – Bangladesh India Triangle : Today : Sterling Publishers, New Delhi, P-1
3. Urvasi Aneja, 'Bangladesh – China Relation : An Emerging Strategic Partnership, IPCS Special report, Nov., P 186
4. World Focus, Sept. P-406
5. Chinese Puzzle in India – Bangladesh Relation, by Anand Kumar, IDSA Publications April 19, P-201
6. थॉमस, डब्ल्यू, ऑन हवेनसांग ट्रेवेल्स इन इण्डिया भाग 2 पृ0–88 मुंशीराम मनोहर लाल, पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0–88
7. वही, पृ0–130
8. सिंह एम.एस. और पी.एस. गुणानन्द, हिस्ट्री ऑफ नेपाल, पृ0 71–75
9. पूर्वोक्त, पृ0–271
10. राइट डी., हिस्ट्री ऑफ ट्रान्सलेटेड फ्रॉम पर्वतीया, पृ0–81